EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

2 - 8 AUG 2026

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

EXAM Genius

UPSC SSC BANK RAILWAY STATE EXAMS

Ques: The Favara payment system, recently integrated with India's UPI, belongs to which country?
प्रश्न: हाल ही में भारत के UPI के साथ एकीकृत किया गया Favara भुगतान प्रणाली किस देश की है?

A) Sri Lanka / श्रीलंका

B) Nepal / नेपाल

C) Maldives / मालदीव

D) Bhutan / भूटान

E) Singapore / सिंगापुर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• NPCI International Payments Ltd. (NIPL) and the Maldives Monetary Authority (MMA) successfully launched the integration of Maldives' instant payment system Favara with India's Unified Payments Interface (UPI).
• NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA) ने मालदीव की इंस्टेंट पेमेंट प्रणाली Favara को भारत के UPI के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया।
• The Favara–UPI corridor enables seamless, secure and faster cross-border digital payments between India and the Maldives.
• Favara–UPI कॉरिडोर भारत और मालदीव के बीच तेज़, सुरक्षित और निर्बाध सीमा-पार डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

UPI (Unified Payments Interface) | यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
• Launched – 2016
• लॉन्च – 2016
• Developed By – National Payments Corporation of India (NPCI)
• विकसितकर्ता – नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)

Maldives | मालदीव
• Capital – Malé
• राजधानी – माले
• Currency – Maldivian Rufiyaa (MVR)
• मुद्रा – मालदीवियन रूफिया (MVR)

Ques: Under the RBI's proposed new securitisation rules, what is the minimum investment limit per investor for securitisation notes?
प्रश्न: RBI के प्रस्तावित नए प्रतिभूतिकरण (Securitisation) नियमों के अनुसार, प्रतिभूतिकरण नोट्स में प्रति निवेशक न्यूनतम निवेश सीमा कितनी होगी?

A) ₹25 lakh
B) ₹50 lakh
C) ₹75 lakh
D) ₹1 crore
E) ₹2 crore

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has proposed new rules requiring all securitisation notes to be issued, held, and transferred only in dematerialised (demat) form.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रस्तावित नए नियमों में सभी प्रतिभूतिकरण (Securitisation) नोट्स को केवल डीमैट (Demat) रूप में जारी करने, रखने और हस्तांतरित करने का प्रावधान किया है।
• Physical paper certificates will no longer be permitted under the proposed framework.
• प्रस्तावित व्यवस्था के तहत भौतिक (कागज़ी) प्रमाणपत्रों की अनुमति नहीं होगी।
• The minimum investment limit of ₹1 crore per investor has been retained. This limit will apply both at the time of initial issuance and for every

subsequent transfer.

• प्रति निवेशक ₹1 करोड़ की न्यूनतम निवेश सीमा को यथावत रखा गया है। यह सीमा प्रारंभिक निर्गम (Initial Issuance) तथा प्रत्येक बाद के हस्तांतरण (Subsequent Transfer) दोनों पर लागू होगी।

• The proposed rules will apply to commercial banks, small finance banks (SFBs), non-banking financial companies (NBFCs), and financial institutions.

• ये प्रस्तावित नियम वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) तथा वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे।

• Public comments on the draft have been invited until 27 August 2026, and the final regulations are proposed to come into effect from 1 October 2026.

• मसौदा नियमों पर 27 अगस्त 2026 तक सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं तथा अंतिम नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Securitisation is the process of converting illiquid financial assets, such as loans, into marketable securities.

• प्रतिभूतिकरण (Securitisation) वह प्रक्रिया है, जिसमें ऋण जैसी अल्प-तरल (Illiquid) वित्तीय परिसंपत्तियों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है।

• Demat (Dematerialised) form means securities are held electronically instead of as physical certificates.

• डीमैट (Dematerialised) रूप का अर्थ है कि प्रतिभूतियाँ कागज़ी प्रमाणपत्रों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाती हैं।

• RBI is the regulator of India's banking system and several segments of the financial market.

• RBI भारत की बैंकिंग प्रणाली तथा वित्तीय बाजार के कई क्षेत्रों का नियामक है।

• Established – 1 April 1935.

• स्थापना – 1 अप्रैल 1935।

Ques: SEBI has extended the deadline for completing digital accessibility audits till which date?

प्रश्न: सेबी ने डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट पूरा करने की समय-सीमा किस तिथि तक बढ़ाई है?

A) 31 July 2026
B) 30 September 2026
C) 31 October 2026
D) 31 December 2026
E) 30 April 2027

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• SEBI has extended the deadline for regulated entities to complete digital accessibility audits and resolve platform-related issues till 31 October 2026.
• सेबी ने विनियमित संस्थाओं के लिए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट पूरा करने और प्लेटफ़ॉर्म संबंधी समस्याओं को दूर करने की समय-सीमा 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है।
• Earlier, the audit completion deadline was 30 April, while the deadline for implementing corrective measures and achieving full compliance was 31 July.
• इससे पहले ऑडिट पूरा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तथा सुधारात्मक उपाय लागू कर पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी।
• The extension was granted after requests from industry stakeholders to allow more time for compliance with the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, ensuring digital platforms are accessible to persons with disabilities.
• यह विस्तार उद्योग जगत की मांग पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act) के प्रावधानों का पालन करने हेतु अधिक समय देने के लिए किया गया है, ताकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बन सकें।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Securities and Exchange Board of India (SEBI) | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

• Established – 12 April 1988
• स्थापना – 12 अप्रैल 1988
• Statutory Status – 30 January 1992 (SEBI Act, 1992)
• वैधानिक दर्जा – 30 जनवरी 1992 (सेबी अधिनियम, 1992)
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Chairperson – Tuhin Kanta Pandey
• अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडेय

Ques: India's foreign exchange reserves recently increased to approximately how much?
प्रश्न: हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर लगभग कितना हो गया?

A) $676.24 Billion
B) $680.00 Billion
C) $682.35 Billion
D) $685.50 Billion
E) $690.00 Billion

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's foreign exchange (Forex) reserves increased by $6.12 billion to $682.35 billion during the week ended 24 July, according to the Reserve Bank of India (RBI).
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, 24 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6.12 बिलियन बढ़कर $682.35 बिलियन हो गया।
• The rise was mainly driven by an increase of $4.87 billion in Foreign Currency Assets (FCAs), which reached $555.93 billion.
• इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण Foreign Currency Assets (FCA) में $4.87 बिलियन की वृद्धि रही, जो बढ़कर $555.93 बिलियन हो गई।

EXAM Genius

• Gold reserves also increased by $1.31 billion, contributing to the overall rise in India's forex reserves.
• स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) में भी $1.31 बिलियन की वृद्धि हुई, जिससे कुल विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Foreign Exchange Reserves (Forex Reserves) | विदेशी मुद्रा भंडार

• Maintained By – Reserve Bank of India (RBI)
• प्रबंधन – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
• Major Components – Foreign Currency Assets (FCA), Gold Reserves, SDRs & Reserve Position in IMF
• प्रमुख घटक – विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA), स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDRs) तथा IMF में रिज़र्व पोज़िशन

Ques: Bajaj Finserv has received board approval to enter which business, subject to IRDAI approval?
प्रश्न: बजाज फिनसर्व को IRDAI की मंजूरी के अधीन किस व्यवसाय में प्रवेश के लिए बोर्ड की स्वीकृति मिली है?

A) Mutual Fund / म्यूचुअल फंड

B) Stock Broking / स्टॉक ब्रोकिंग

C) Reinsurance / पुनर्बीमा

D) Asset Management / एसेट मैनेजमेंट

E) General Banking / सामान्य बैंकिंग

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Bajaj Finserv's Board has approved the company's entry into the reinsurance business, subject to approval from the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).

• बजाज फिनसर्व के बोर्ड ने IRDAI की मंजूरी के अधीन कंपनी के पुनर्बीमा (Reinsurance) व्यवसाय में प्रवेश को स्वीकृति दी है।

• The company will enter the reinsurance sector through a wholly-owned subsidiary, becoming the third private player to announce plans to enter India's domestic reinsurance market in about a year.

• कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (Wholly-Owned Subsidiary) के माध्यम से पुनर्बीमा क्षेत्र में प्रवेश करेगी और लगभग एक वर्ष में ऐसा करने की घोषणा करने वाली तीसरी निजी कंपनी बन गई है।

• The move is expected to increase competition in India's reinsurance market, which opened to private participation after the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

• इस कदम से भारत के पुनर्बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है, जिसे बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के बाद निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Bajaj Finserv Ltd. | बजाज फिनसर्व लिमिटेड

• Founded – 2007
• स्थापना – 2007
• Headquarters – Pune, Maharashtra
• मुख्यालय – पुणे, महाराष्ट्र
• Sector – Financial Services (Insurance, Lending & Investments)
• क्षेत्र – वित्तीय सेवाएँ (बीमा, ऋण एवं निवेश)

Ques: K. Rajaraman's tenure as Chairperson of IFSCA has been extended till which year?

प्रश्न: के. राजारामन का IFSCA के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाया गया है?

A) 2026
B) 2027
C) 2028
D) 2029
E) 2030

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Central Government has extended the tenure of K. Rajaraman as the Chairperson of the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) till October 2028 or until further orders, whichever is earlier.
• केंद्र सरकार ने के. राजारामन का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल अक्टूबर 2028 तक या अगले आदेश तक (जो पहले हो) बढ़ा दिया है।
• K. Rajaraman has been serving as the Chairperson of IFSCA since 1 August 2023 and will continue to lead India's unified regulator for financial services in IFSCs.
• के. राजारामन 1 अगस्त 2023 से IFSCA के अध्यक्ष हैं और अब भारत के IFSCs के एकीकृत वित्तीय नियामक का नेतृत्व जारी रखेंगे।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

International Financial Services Centres Authority (IFSCA) | अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)

• Established – 2020
• स्थापना – 2020
• Headquarters – GIFT City, Gandhinagar, Gujarat
• मुख्यालय – GIFT City, गांधीनगर, गुजरात

Ques: What is the repo rate that the RBI's Monetary Policy Committee is

expected to maintain in its August 2026 meeting?
प्रश्न: अगस्त 2026 की बैठक में RBI की MPC द्वारा किस रेपो रेट को बनाए रखने की संभावना है?

A) 4.75%
B) 5.00%
C) 5.25%
D) 5.50%
E) 6.00%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The RBI's Monetary Policy Committee (MPC) is expected to keep the repo rate unchanged at 5.25% and maintain its neutral stance during the 3–5 August 2026 policy meeting.
• RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 3–5 अगस्त 2026 की बैठक में रेपो रेट 5.25% पर अपरिवर्तित रखने तथा तटस्थ रुख (Neutral Stance) बनाए रखने की संभावना है।
• The MPC has kept the repo rate unchanged in its last three meetings while maintaining a neutral stance for six consecutive meetings.
• MPC ने अपनी पिछली तीन बैठकों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि लगातार छह बैठकों से तटस्थ रुख बनाए रखा है।
• Retail inflation rose from 3.9% in May 2026 to 4.4% in June 2026, crossing the RBI's 4% inflation target and increasing pressure on monetary policy.
• खुदरा महंगाई मई 2026 के 3.9% से बढ़कर जून 2026 में 4.4% हो गई, जिससे यह RBI के 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर पहुंच गई और मौद्रिक नीति पर दबाव बढ़ा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Monetary Policy Committee (MPC) | मौद्रिक नीति समिति (MPC)

• Established – 2016

• स्थापना – 2016
• Total Members – 6
• कुल सदस्य – 6
• Chairperson – RBI Governor
• अध्यक्ष – RBI गवर्नर
• Main Function – To decide the Policy Repo Rate and help achieve the inflation target
• मुख्य कार्य – नीति रेपो रेट निर्धारित करना तथा मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करना
• Inflation Target – 4% ± 2%
• मुद्रास्फीति लक्ष्य – 4% ± 2%

Current RBI Policy Rates | वर्तमान RBI नीति दरें

• Repo Rate – 5.25%
• रेपो रेट – 5.25%
• SDF Rate – 5.00%
• SDF दर – 5.00%
• MSF Rate – 5.50%
• MSF दर – 5.50%
• Bank Rate – 5.50%
• बैंक दर – 5.50%

Ques: Which company has received IRDAI approval to acquire a majority stake (73.56%) in Magma General Insurance?
प्रश्न: किस कंपनी को IRDAI से मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में 73.56% बहुलांश हिस्सेदारी (Majority Stake) अधिग्रहित करने की मंजूरी मिली है?

A) Aditya Birla Capital / आदित्य बिड़ला कैपिटल

B) Patanjali Ayurved / पतंजलि आयुर्वेद

C) Reliance Industries / रिलायंस इंडस्ट्रीज़

D) Tata AIG / टाटा एआईजी

E) Bajaj Finserv / बजाज फिनसर्व

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has approved the acquisition of Magma General Insurance by Patanjali Ayurved and DS Group from Adar Poonawalla-owned Sanoti Properties.
• भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अदार पूनावाला के स्वामित्व वाली सनोटी प्रॉपर्टीज़ से पतंजलि आयुर्वेद और डीएस ग्रुप द्वारा मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
• Patanjali Ayurved will acquire a 73.56% stake in Magma General Insurance.
• पतंजलि आयुर्वेद मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में 73.56% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा।
• DS Group-associated foundations will acquire about 24.50% stake.
• डीएस ग्रुप से संबद्ध फाउंडेशन लगभग 24.50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगे।
• Together, Patanjali Ayurved and DS Group will acquire a total 98.055% stake in the company.
• पतंजलि आयुर्वेद और डीएस ग्रुप मिलकर कंपनी में कुल 98.055% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगे।
• Sanoti Properties had announced the sale of its stake in Magma General Insurance to Patanjali Ayurved and DS Group for ₹4,500 crore.
• सनोटी प्रॉपर्टीज़ ने ₹4,500 करोड़ में मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी पतंजलि आयुर्वेद और डीएस ग्रुप को बेचने की घोषणा की थी।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• IRDAI stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India.
• IRDAI का पूर्ण रूप भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण है।
• IRDAI was established in 1999 under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.
• IRDAI की स्थापना 1999 में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत हुई थी।
• Headquarters – Hyderabad, Telangana.

• मुख्यालय – हैदराबाद, तेलंगाना।
• IRDAI regulates and supervises the insurance sector in India to protect policyholders' interests and ensure the orderly growth of the insurance industry.
• IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करता है तथा पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा और बीमा उद्योग के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करता है।

Ques: What is the value of Zee Entertainment's fundraising plan approved by its shareholders in July 2026?
प्रश्न: जुलाई 2026 में Zee Entertainment के शेयरधारकों द्वारा मंजूर फंडरेजिंग योजना का मूल्य कितना है?

A) ₹2,143.5 crore
B) ₹2,843.5 crore
C) ₹3,143.5 crore
D) ₹3,543.5 crore
E) ₹4,143.5 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• SEBI barred Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) from accessing the securities market for 2 months in connection with the unauthorised pledging of company property.
• SEBI ने कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत गिरवीकरण के मामले में Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) को 2 महीने के लिए प्रतिभूति बाजार (Securities Market) से प्रतिबंधित कर दिया।
• SEBI also barred Subhash Chandra and Punit Goenka from accessing the securities market for 12 months.
• SEBI ने सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका को भी 12 महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया।
• On 31 July 2026, Zee Entertainment's shareholders approved a ₹3,143.5

crore preferential issue of fully convertible warrants.

• 31 जुलाई 2026 को Zee Entertainment के शेयरधारकों ने ₹3,143.5 करोड़ के पूर्ण रूप से परिवर्तनीय वारंट (Fully Convertible Warrants) के प्रेफरेंशियल इश्यू को मंजूरी दी।

• The proposed fundraise is expected to increase the promoter group's stake in the company to 23.79%.

• इस फंडरेजिंग के बाद कंपनी में प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी बढ़कर 23.79% होने की उम्मीद है।

• Zee Entertainment stated that the SEBI order has no direct impact on the ongoing fundraising process and that it will take all necessary steps to complete the issue.

• Zee Entertainment ने स्पष्ट किया कि SEBI के आदेश का उसकी चल रही फंडरेजिंग प्रक्रिया पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा और कंपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

SEBI (Securities and Exchange Board of India) | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

• Established – 1988
• स्थापना – 1988
• Statutory Status – 1992 (SEBI Act, 1992)
• वैधानिक दर्जा – 1992 (सेबी अधिनियम, 1992)
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• Chairman – Tuhin Kanta Pandey
• अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडे

Ques: OmniCard, operated by Eroute Technologies Private Limited, has launched India's first what on the UPI platform?

प्रश्न: Eroute Technologies Private Limited द्वारा संचालित OmniCard ने UPI

प्लेटफॉर्म पर भारत का पहला क्या लॉन्च किया है?

A) Flexi Benefits Basket / फ्लेक्सी बेनिफिट्स बास्केट

B) Digital Salary Account / डिजिटल वेतन खाता

C) UPI Credit Wallet / यूपीआई क्रेडिट वॉलेट

D) Employee Rewards Card / कर्मचारी रिवॉर्ड्स कार्ड

E) Corporate Expense Wallet / कॉर्पोरेट व्यय वॉलेट

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• OmniCard, operated by Eroute Technologies Private Limited, has launched what it describes as India's first Flexi Benefits Basket on UPI.

• Eroute Technologies Private Limited द्वारा संचालित OmniCard ने UPI पर भारत का पहला फ्लेक्सी बेनिफिट्स बास्केट लॉन्च किया है।

• The platform combines multiple employer-provided benefits into a single employee-controlled digital wallet.

• यह प्लेटफॉर्म नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों को एक कर्मचारी-नियंत्रित डिजिटल वॉलेट में एकीकृत करता है।

• Employees can allocate and spend their benefit allowance seamlessly through the UPI ecosystem.

• कर्मचारी अपने लाभ भत्ते (Benefit Allowance) का आवंटन और उपयोग सीधे UPI के माध्यम से कर सकते हैं।

• The initiative aims to simplify employee benefits management while offering greater flexibility and convenience in spending.

• इस पहल का उद्देश्य कर्मचारी लाभ प्रबंधन को सरल बनाना तथा लाभ राशि के उपयोग में अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करना है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• UPI (Unified Payments Interface) is a real-time digital payment system developed by the National Payments Corporation of India (NPCI).

• UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) एक रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित किया है।
• NPCI was established in 2008.
• NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी।
• Headquarters of NPCI – Mumbai, Maharashtra.
• NPCI का मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।
• UPI enables instant fund transfers between bank accounts using mobile devices, 24×7.
• UPI मोबाइल के माध्यम से बैंक खातों के बीच 24×7 त्वरित धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

Ques: Which Bill has been introduced to replace the Bankers' Books Evidence Act, 1891?
प्रश्न: Bankers' Books Evidence Act, 1891 को बदलने के लिए कौन-सा विधेयक पेश किया गया है?

A) Banking Regulation Amendment Bill, 2026 / बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक, 2026
B) Digital Banking Evidence Bill, 2026 / डिजिटल बैंकिंग एविडेंस विधेयक, 2026
C) Bankers' Books Evidence Bill, 2026 / बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026
D) Banking Records Protection Bill, 2026 / बैंकिंग रिकॉर्ड्स प्रोटेक्शन विधेयक, 2026
E) Financial Evidence Bill, 2026 / फाइनेंशियल एविडेंस विधेयक, 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Government has introduced the Bankers' Books Evidence Bill, 2026 in Parliament to replace the Bankers' Books Evidence Act, 1891.
• सरकार ने Bankers' Books Evidence Act, 1891 को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद

में Bankers’ Books Evidence Bill, 2026 पेश किया है।

• The Bill seeks to recognise physical, electronic, digital, virtual and cloud-based banking records as admissible evidence in courts.

• इस विधेयक के तहत भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल तथा क्लाउड-आधारित बैंकिंग रिकॉर्ड को अदालतों में साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाएगी।

• It introduces the concept of “Special Cause”, allowing courts to access banking records when justified while reducing unnecessary summons to bank officials.

• इसमें “Special Cause” की अवधारणा शामिल की गई है, जिसके तहत विशेष कारण होने पर अदालत बैंकिंग रिकॉर्ड मंगा सकेगी तथा बैंक अधिकारियों को अनावश्यक रूप से अदालत में बुलाने की आवश्यकता कम होगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Bankers’ Books Evidence Act, 1891 | बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 1891

• Original Law – Bankers’ Books Evidence Act, 1891
• मूल कानून – बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 1891
• New Bill – Bankers’ Books Evidence Bill, 2026
• नया विधेयक – बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, 2026

Ques: What is the name of the new mutual fund transaction platform launched by the National Commodity and Derivatives Exchange Limited (NCDEX)?

प्रश्न: नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) द्वारा शुरू किए गए नए म्यूचुअल फंड लेनदेन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?

A) NCDEX Invest / एनसीडीईएक्स इन्वेस्ट

B) NCDEX Nidhi / एनसीडीईएक्स निधि

C) FPO Mutual Connect / एफपीओ म्यूचुअल कनेक्ट

D) Bharat MF Portal / भारत एमएफ पोर्टल

E) Nivesh Setu / निवेश सेतु

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• India's mutual fund industry has taken another step towards financial inclusion with the launch of NCDEX Nidhi, a new mutual fund transaction platform by the National Commodity and Derivatives Exchange Limited (NCDEX).

• भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग ने वित्तीय समावेशन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) द्वारा NCDEX Nidhi नामक नया म्यूचुअल फंड लेनदेन प्लेटफॉर्म शुरू किया है।

• NCDEX plans to leverage its network of around 800 Farmer Producer Organisations (FPOs) to expand mutual fund distribution across rural India.

• NCDEX म्यूचुअल फंड वितरण का विस्तार करने के लिए लगभग 800 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के अपने नेटवर्क का उपयोग करेगा।

• Each FPO has an average membership of about 250 farmers, creating an opportunity to introduce mutual funds to first-time investors.

• प्रत्येक FPO में औसतन 250 सदस्य हैं, जिससे पहली बार निवेश करने वाले लोगों तक म्यूचुअल फंड पहुँचाने का बड़ा अवसर मिलेगा।

• The platform has initially onboarded 6 Asset Management Companies (AMCs).

• इस प्लेटफॉर्म पर प्रारंभिक चरण में 6 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को शामिल किया गया है।

• The initiative aims to promote financial inclusion by making mutual fund investments more accessible in rural and agricultural communities.

• इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और कृषि समुदायों में म्यूचुअल फंड निवेश को अधिक सुलभ बनाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• NCDEX stands for National Commodity and Derivatives Exchange Limited.

• NCDEX का पूर्ण रूप नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड है।

• Established – 2003.

• स्थापना – 2003।
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।
• MD & CEO – Vikas Goel
• प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) –विकास गोयल

Ques: How much forex inflow was attracted through RBI's concessional forex swap facility till 31 July 2026?

प्रश्न: 31 जुलाई 2026 तक RBI की रियायती फॉरेक्स स्वैप सुविधा के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा जुटाई गई?

A) $30.82 billion
B) $35.72 billion
C) $40.82 billion
D) $45.82 billion
E) $50.82 billion

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The RBI's concessional forex swap facility, introduced to encourage foreign currency inflows, attracted $40.82 billion till 31 July 2026.
• विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई RBI की रियायती फॉरेक्स स्वैप सुविधा के तहत 31 जुलाई 2026 तक $40.82 बिलियन की राशि जुटाई गई।
• FCNR(B) deposits accounted for the largest share at $36.725 billion, while OFCBs contributed $2.575 billion.
• कुल प्रवाह में FCNR(B) जमा की हिस्सेदारी सबसे अधिक $36.725 बिलियन रही, जबकि OFCBs से $2.575 बिलियन प्राप्त हुए।
• External Commercial Borrowings (ECBs) contributed $1.516 billion, with the facility attracting steady forex inflows since 8 June 2026.
• External Commercial Borrowings (ECBs) के माध्यम से $1.516 बिलियन प्राप्त हुए

और 8 जून 2026 से इस सुविधा के तहत लगातार विदेशी मुद्रा प्रवाह दर्ज किया गया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

RBI Concessional Forex Swap Facility | RBI की रियायती फॉरेक्स स्वैप सुविधा

- Introduced – 8 June 2026
- प्रारंभ – 8 जून 2026
- Purpose – To encourage foreign currency inflows and strengthen India's external sector
- उद्देश्य – विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देना तथा भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना
- Total Forex Inflow (Till 31 July 2026) – $40.82 billion
- कुल विदेशी मुद्रा प्रवाह (31 जुलाई 2026 तक) – $40.82 बिलियन
- FCNR(B) Deposits – $36.725 billion
- FCNR(B) जमा – $36.725 बिलियन
- OFCBs – $2.575 billion
- OFCBs – $2.575 बिलियन
- ECBs (External Commercial Borrowings) – $1.516 billion
- ECBs (बाह्य वाणिज्यिक उधार) – $1.516 बिलियन

Ques: Which three banks together received nearly half of the total FCNR(B) inflows under the RBI's 2026 deposit scheme?
प्रश्न: RBI की 2026 FCNR(B) जमा योजना के तहत कुल FCNR(B) प्रवाह का लगभग आधा हिस्सा किन तीन बैंकों को प्राप्त हुआ?

A) HDFC Bank, Axis Bank & Kotak Mahindra Bank / HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक

B) SBI, Bank of Baroda & Punjab National Bank / SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं पंजाब नेशनल बैंक

C) HSBC, SBI & ICICI Bank / HSBC, SBI एवं ICICI बैंक

D) HSBC, Standard Chartered & HDFC Bank / HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एवं HDFC बैंक

E) ICICI Bank, Axis Bank & Bank of Baroda / ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Banks received $36.7 billion under the RBI's FCNR(B) deposit scheme till 31 July 2026 to strengthen foreign exchange inflows.

• RBI की FCNR(B) जमा योजना के तहत 31 जुलाई 2026 तक बैंकों को $36.7 बिलियन की विदेशी मुद्रा जमा प्राप्त हुई।

• HSBC ($6.1 billion), SBI ($4.1 billion) and ICICI Bank ($3.7 billion) together accounted for nearly half of the total FCNR(B) inflows.

• HSBC ($6.1 बिलियन), SBI ($4.1 बिलियन) और ICICI बैंक ($3.7 बिलियन) को मिलाकर कुल FCNR(B) प्रवाह का लगभग आधा हिस्सा प्राप्त हुआ।

• The RBI launched the FCNR(B) scheme in June 2026 to attract foreign currency deposits from NRIs and strengthen India's forex reserves and banking liquidity.

• RBI ने जून 2026 में FCNR(B) योजना शुरू की, ताकि NRI से विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित कर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और बैंकिंग तरलता को मजबूत किया जा सके।

EXAM Genius

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• FCNR(B) – Foreign Currency Non-Resident (Bank)
• FCNR(B) – फॉरेन करेंसी नॉन-रेज़िडेंट (बैंक)
• Reserve Bank of India (RBI) – Established: 1 April 1935
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) – स्थापना: 1 अप्रैल 1935
• NRI – Non-Resident Indian
• NRI – अनिवासी भारतीय
• Forex Reserves – Foreign Exchange Reserves
• विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) – Foreign Exchange Reserves

• State Bank of India (SBI) – India's Largest Public Sector Bank
• भारतीय स्टेट बैंक (SBI) – भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक

Ques: Since which year have investments from countries sharing a land border with India required prior Government approval under Press Note 3?
प्रश्न: भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश के लिए Press Note 3 के तहत सरकार की पूर्व मंजूरी किस वर्ष से अनिवार्य है?

A) 2018
B) 2019
C) 2020
D) 2021
E) 2022

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India approved only one Chinese Foreign Direct Investment (FDI) proposal worth ₹1 crore during FY 2025–26.
• भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में चीन से केवल ₹1 करोड़ के एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्ताव को मंजूरी दी।
• During the same period, 13 FDI proposals from Hong Kong worth ₹610.42 crore were approved.
• इसी अवधि में हांगकांग से ₹610.42 करोड़ के 13 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
• Since April 2020, investments from countries sharing a land border with India require prior Government approval under Press Note 3 issued by DPIIT.
• अप्रैल 2020 से भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश के लिए DPIIT के Press Note 3 के तहत सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
• The policy was introduced to safeguard strategic sectors while regulating foreign investments from neighbouring countries.
• इस नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों से आने वाले विदेशी निवेश को विनियमित करते हुए

रणनीतिक क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Foreign Direct Investment (FDI) | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- Meaning – Investment made by a foreign entity in the business of another country.
- अर्थ – किसी विदेशी संस्था द्वारा दूसरे देश के व्यवसाय में किया गया प्रत्यक्ष निवेश।

Press Note 3 | प्रेस नोट 3

- Effective – April 2020
- लागू – अप्रैल 2020
- Issued By – DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
- जारीकर्ता – DPIIT (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)

DPIIT | Department for Promotion of Industry and Internal Trade | उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

- Ministry – Ministry of Commerce & Industry
- मंत्रालय – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- Headquarters – New Delhi
- मुख्यालय – नई दिल्ली

Ques: According to NSDL data, how much net debt investment did Foreign Portfolio Investors (FPIs) make after the RBI's June 2026 policy?

प्रश्न: NSDL के अनुसार, RBI की जून 2026 की नीति के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने ऋण (Debt) बाजार में कितना शुद्ध निवेश किया?

A) $2.34 billion
B) $4.50 billion
C) $6.11 billion
D) $8.44 billion
E) $10.25 billion

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Following the RBI's June 2026 Monetary Policy announcement, Foreign Portfolio Investors (FPIs) invested around $8.44 billion in India's debt and equity markets.

• RBI की जून 2026 की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारत के ऋण और इक्विटी बाजार में लगभग $8.44 बिलियन का निवेश किया।

• According to NSDL, FPIs were net buyers of $6.11 billion in the debt market and $2.34 billion in the domestic equity market during this period.

• NSDL के अनुसार, इस अवधि में FPIs ने ऋण (Debt) बाजार में $6.11 बिलियन तथा घरेलू इक्विटी (Equity) बाजार में $2.34 बिलियन का शुद्ध निवेश किया।

• To encourage foreign investment, the Government exempted certain Government Securities from taxes for foreign investors.

• विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) पर विदेशी निवेशकों को कर छूट प्रदान की।

• RBI also expanded the Fully Accessible Route (FAR) to include new 15-year, 30-year and 40-year Government Securities.

• RBI ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए Fully Accessible Route (FAR) का दायरा नई 15 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष की सरकारी प्रतिभूतियों तक बढ़ा दिया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Foreign Portfolio Investor (FPI) | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

• Meaning – Investor investing in financial assets such as shares and bonds in another country.

• अर्थ – ऐसा निवेशक जो किसी अन्य देश के शेयर, बॉन्ड और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करता है।

National Securities Depository Limited (NSDL) | नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

• Established – 1996
• स्थापना – 1996
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

Fully Accessible Route (FAR) | फुली एक्सेसिबल रूट
• Introduced – 2020
• प्रारंभ – 2020
• Purpose – To allow eligible foreign investors to invest in specified Government Securities without investment limits.
• उद्देश्य – पात्र विदेशी निवेशकों को निर्धारित सरकारी प्रतिभूतियों में बिना निवेश सीमा के निवेश की अनुमति देना।

Ques: Monisha Chakraborty has been appointed as Executive Director of which organisation?
प्रश्न: मोनिषा चक्रवर्ती को किस संगठन का कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया गया है?

A) SEBI / सेबी
B) NABARD / नाबार्ड
C) RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक
D) SIDBI / सिडबी
E) IRDAI / आईआरडीएआई

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has appointed Monisha Chakraborty as Executive Director (ED) with effect from 3 August 2026.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 3 अगस्त 2026 से मोनिषा चक्रवर्ती को कार्यकारी

निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया है।

• She will oversee the Foreign Exchange Department and the Financial Markets Regulation Department.

• वे विदेशी मुद्रा विभाग (Foreign Exchange Department) तथा वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (Financial Markets Regulation Department) का कार्यभार संभालेंगी।

• A career central banker with over 30 years of experience, she earlier served as Chief General Manager-in-Charge of the Department of Supervision and has also worked as a Banking Ombudsman.

• 30 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाली मोनिषा चक्रवर्ती इससे पहले विभागीय पर्यवेक्षण (Department of Supervision) में चीफ जनरल मैनेजर-इन-चार्ज थीं तथा बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं।

• Before her promotion, she served as Chief General Manager-in-Charge of the Department of Supervision and has over three decades of experience in the RBI.

• पदोन्नति से पहले वे विभागीय पर्यवेक्षण में चीफ जनरल मैनेजर-इन-चार्ज थीं और उन्हें RBI में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।

Ques: According to the accepted recommendation of the 16th Finance Commission, what is the States' vertical share in the Centre's divisible pool of taxes?

प्रश्न: 16वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार, केंद्र के विभाज्य कर पूल (Divisible Pool) में राज्यों की ऊर्ध्वाधर (Vertical) हिस्सेदारी कितनी है?

A) 35%
B) 38%
C) 40%
D) 41%
E) 42%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Union Government released an **additional tax devolution instalment of ₹1,09,019 crore** to State Governments on **1 August 2026**.

• केंद्र सरकार ने **1 अगस्त 2026** को राज्यों को **₹1,09,019 करोड़** की अतिरिक्त कर हस्तांतरण (Tax Devolution) की किस्त जारी की।

• This amount was released in addition to the regular monthly tax devolution scheduled for **10 August 2026**.

• यह राशि **10 अगस्त 2026** को जारी होने वाली नियमित मासिक कर हस्तांतरण राशि के अतिरिक्त है।

• **Uttar Pradesh** received the highest share of **₹19,208 crore**, followed by **Bihar (₹10,845 crore)** and **Madhya Pradesh (₹8,010 crore)**.

• **उत्तर प्रदेश** को सबसे अधिक **₹19,208 करोड़**, इसके बाद **बिहार (₹10,845 करोड़)** और **मध्य प्रदेश (₹8,010 करोड़)** प्राप्त हुए।

• **Tax Devolution** refers to the transfer of the prescribed share of the Centre's divisible pool of taxes to the State Governments as provided under the Constitution.

• **कर हस्तांतरण (Tax Devolution)** का अर्थ है संविधान के अनुसार केंद्र के विभाज्य कर पूल से राज्यों को निर्धारित हिस्से का हस्तांतरण।

• The Union Government has accepted the **16th Finance Commission's** recommendation to retain the **States' vertical share at 41%** of the divisible pool.

• केंद्र सरकार ने **16वें वित्त आयोग** की उस सिफारिश को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार विभाज्य कर पूल में **राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी** 41% बनी रहेगी।

• The tax devolution amount is distributed among States in **14 instalments** during a financial year.

• वित्तीय वर्ष के दौरान कर हस्तांतरण की राशि राज्यों को 14 **किस्तों** में वितरित की जाती है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• The **Finance Commission** is constituted under **Article 280** of the Constitution of India.

• **वित्त आयोग** का गठन भारतीय संविधान के **अनुच्छेद** 280 के तहत किया जाता है।

• The Finance Commission recommends the distribution of tax revenues

between the **Union and the States**.

• वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।

• The **Divisible Pool** consists of those central taxes that are shared with the States as per the Finance Commission's recommendations.

• **विभाज्य कर पूल (Divisible Pool)** में वे केंद्रीय कर शामिल होते हैं, जिन्हें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

• Tax devolution strengthens **fiscal federalism** by ensuring predictable financial resources for State Governments.

• कर हस्तांतरण सहकारी संघवाद (Fiscal Federalism) को मजबूत करता है तथा राज्यों को नियमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है।

Ques: Which state retained the top position in the growth of post-settlement SGST collections during the first four months of FY 2026–27?

प्रश्न: वित्त वर्ष 2026–27 के पहले चार महीनों में पोस्ट-सेटलमेंट SGST संग्रह की वृद्धि में किस राज्य ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा?

A) Gujarat / गुजरात

B) Maharashtra / महाराष्ट्र

C) Karnataka / कर्नाटक

D) Haryana / हरियाणा

E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

EXAM Genius

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Haryana retained the top position in the growth of post-settlement State Goods and Services Tax (SGST) collections during the first four months of FY 2026–27.

• हरियाणा ने वित्त वर्ष 2026–27 के पहले चार महीनों में पोस्ट-सेटलमेंट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) संग्रह की वृद्धि में देश में पहला स्थान बरकरार रखा।

• According to the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Haryana's post-settlement SGST collections increased from ₹4,027 crore in July 2025 to ₹5,135 crore in July 2026.
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अनुसार, हरियाणा का पोस्ट-सेटलमेंट SGST संग्रह जुलाई 2025 के ₹4,027 करोड़ से बढ़कर जुलाई 2026 में ₹5,135 करोड़ हो गया।
• Haryana recorded a 28% year-on-year growth, which was more than double the national average growth of 13%.
• हरियाणा ने 28% वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो 13% के राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी अधिक रही।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) | केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
• Established – 1964 (as Central Board of Excise & Customs)
• स्थापना – 1964 (केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में)
• Renamed – 2018
• नाम परिवर्तित – 2018
• Parent Ministry – Ministry of Finance (Department of Revenue)
• मूल मंत्रालय – वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
• Headquarters – New Delhi
• मुख्यालय – नई दिल्ली

EXAM Genius

Ques: Prasanta Mahapatra has been appointed as the Executive Director of which organisation?
प्रश्न: प्रशांत महापात्र को किस संगठन का कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया गया है?

A) RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक

B) IRDAI / भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

C) SEBI / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

D) PFRDA / पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• SEBI has appointed Prasanta Mahapatra as its new Executive Director (ED).

• सेबी (SEBI) ने प्रशांत महापात्र को नया कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया।

• Based in Mumbai, he will oversee the Corporation Finance Investigation Department and the Recovery & Refund Department.

• मुंबई स्थित महापात्र कॉरपोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन विभाग तथा रिकवरी एवं रिफंड विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

• Mahapatra has been associated with SEBI since April 1999 and previously served as Chief General Manager. He has worked in Market Regulation, Investigation, Investment Management and other key departments.

• महापात्र अप्रैल 1999 से SEBI से जुड़े हुए हैं और इससे पहले चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने मार्केट रेगुलेशन, जांच, निवेश प्रबंधन सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया है।

• Mahapatra has extensive experience in regulatory, investigation and investment management functions, making him well suited for his new leadership role at SEBI.

• महापात्र को नियामक, जांच तथा निवेश प्रबंधन से जुड़े कार्यों का व्यापक अनुभव है, जो उन्हें SEBI में नई नेतृत्वकारी जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• SEBI – Securities and Exchange Board of India

• SEBI – भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

• Established – 1988

• स्थापना – 1988

• Statutory Status – 1992

• वैधानिक दर्जा – 1992
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• Chairperson – Tuhin Kanta Pandey
• अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडे

Ques: GST was introduced in India through which Constitutional Amendment Act?
प्रश्न: भारत में GST किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था?

A) 100th Constitutional Amendment Act, 2015 / 100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2015
B) 101st Constitutional Amendment Act, 2016 / 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
C) 102nd Constitutional Amendment Act, 2018 / 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018
D) 103rd Constitutional Amendment Act, 2019 / 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019
E) 104th Constitutional Amendment Act, 2020 / 104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2020

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The gross Goods and Services Tax (GST) collection surged by **15.4%** to **over ₹2.11 lakh crore** in **July**.
• जुलाई में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का सकल संग्रह **15.4%** बढ़कर **₹2.11 लाख करोड़** से अधिक हो गया।

• GST was officially launched across India on **1 July 2017**.

• GST को पूरे भारत में **1 जुलाई 2017** को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था।

• GST was introduced through the **Constitution (101st Amendment) Act, 2016**.

• GST को **संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016** के माध्यम से लागू किया गया।

• Based on the recommendations of the **56th GST Council Meeting**, the earlier four major GST slabs of **5%, 12%, 18%, and 28%** were rationalised.

• **56वीं GST परिषद** की सिफारिशों के आधार पर पहले की प्रमुख GST दरों **5%, 12%, 18% और 28%** का युक्तिकरण (Rationalisation) किया गया।

• **GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number)** is a **15-digit** identification number issued to registered taxpayers.

• **GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number)** पंजीकृत करदाताओं को जारी किया जाने वाला **15 अंकों** का पहचान संख्या है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• **GST** stands for **Goods and Services Tax**.

• **GST** का पूर्ण रूप **वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax)** है।

• The **GST Council** is chaired by the **Union Finance Minister**.

• **GST परिषद** की अध्यक्षता **केंद्रीय वित्त मंत्री** करते हैं।

• **Article 279A** of the Constitution provides for the constitution of the **GST Council**.

• संविधान का **अनुच्छेद 279A GST परिषद** के गठन का प्रावधान करता है।

• GST replaced multiple indirect taxes such as **VAT, Excise Duty, and Service Tax**, creating a unified indirect tax system in India.

• GST ने **VAT, उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और सेवा कर (Service Tax)** जैसे अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेकर भारत में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था स्थापित की।

Ques: The Government plans to sell up to what percentage stake in LIC through the Offer for Sale (OFS)?

प्रश्न: सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से LIC में अधिकतम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है?

A) 4.5%

B) 5.0%
C) 5.5%
D) 6.5%
E) 7.5%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India will sell up to a 6.5% stake in LIC through an Offer for Sale (OFS) to raise around ₹31,000 crore.
• भारत सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से LIC में 6.5% तक हिस्सेदारी बेचकर लगभग ₹31,000 करोड़ जुटाएगी।
• The floor price has been fixed at ₹382 per share. The issue opens for non-retail investors on 4 August 2026 and retail investors on 5 August 2026.
• फ्लोर प्राइस ₹382 प्रति शेयर तय किया गया है। यह निर्गम 4 अगस्त 2026 को गैर-खुदरा निवेशकों तथा 5 अगस्त 2026 को खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा।
• The sale involves over 82.22 crore shares and aims to help the Government achieve the Minimum Public Shareholding (MPS) requirement.
• इस बिक्री में 82.22 करोड़ से अधिक शेयर शामिल हैं तथा इसका उद्देश्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) की आवश्यकता को पूरा करना है।
• The disinvestment will help the Government meet the Minimum Public Shareholding (MPS) norms while increasing public participation in LIC.
• यह विनिवेश सरकार को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) के मानकों को पूरा करने में मदद करेगा तथा LIC में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाएगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• LIC – Life Insurance Corporation of India
• LIC – भारतीय जीवन बीमा निगम
• Established – 1956
• स्थापना – 1956
• OFS – Offer for Sale
• OFS – ऑफर फॉर सेल

• DIPAM – Department of Investment and Public Asset Management
• DIPAM – निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
• MPS – Minimum Public Shareholding (25%)
• MPS – न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (25%)

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) has postponed the implementation of the revised Basel Pillar III Disclosure Framework for banks to which date?
प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए संशोधित बेसल पिलर III प्रकटीकरण ढाँचे (Basel Pillar III Disclosure Framework) के कार्यान्वयन को किस तिथि तक स्थगित किया है?

A) 1 October 2026
B) 1 January 2027
C) 1 April 2027
D) 1 July 2027
E) 1 October 2027

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has postponed the implementation of the revised Basel Pillar III Disclosure Framework for banks by six months, and it will now come into effect from 1 April 2027.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए संशोधित बेसल पिलर III प्रकटीकरण ढाँचे के कार्यान्वयन को छह महीने के लिए स्थगित कर दिया है। अब यह 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा।
• The framework was originally proposed to be implemented from the quarter ending 30 September 2026.
• यह ढाँचा पहले 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही से लागू किया जाना प्रस्तावित था।
• RBI deferred the implementation following implementation-related

difficulties raised by stakeholders.

• हितधारकों द्वारा कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयाँ उठाए जाने के बाद RBI ने इसकी समय-सीमा बढ़ा दी।

• Pillar III of the Basel Framework aims to promote market discipline through enhanced regulatory disclosure requirements.

• बेसल फ्रेमवर्क का पिलर III नियामकीय प्रकटीकरण (Regulatory Disclosure) के माध्यम से बाज़ार अनुशासन (Market Discipline) को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।

• Basel III disclosures include risk-based capital ratios, leverage ratio, liquidity standards, risk management approach, and risk-weighted assets.

• बेसल III प्रकटीकरण में जोखिम-आधारित पूंजी अनुपात, लीवरेज अनुपात, तरलता मानक, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तथा जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (Risk-Weighted Assets) से संबंधित जानकारी शामिल होती है।

• The first quarterly disclosure will be for the quarter ending 30 June 2027, the first semi-annual disclosure for the half-year ending 30 September 2027, and the first annual disclosure for the financial year ending 31 March 2028.

• पहला त्रैमासिक प्रकटीकरण 30 जून 2027, पहला अर्धवार्षिक प्रकटीकरण 30 सितंबर 2027, तथा पहला वार्षिक प्रकटीकरण 31 मार्च 2028 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किया जाएगा।

• RBI has also exempted public sector banks from disclosing the remuneration of their Chief Executives and reduced the mandatory archive period for Pillar III reports on bank websites from 10 years to at least 5 years.

• RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनके मुख्य कार्यपालक (Chief Executive) के पारिश्रमिक के प्रकटीकरण से छूट दी है तथा बैंक वेबसाइटों पर पिलर III रिपोर्टों की अनिवार्य अभिलेख अवधि 10 वर्ष से घटाकर कम-से-कम 5 वर्ष कर दी है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Basel III is a global regulatory framework developed by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) to strengthen the regulation, supervision and risk management of banks.

• बेसल III बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु बेसल समिति ऑन बैंकिंग सुपरविजन (BCBS) द्वारा विकसित वैश्विक नियामक ढाँचा है।

• The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) was established in 1974.

• बेसल समिति ऑन बैंकिंग सुपरविजन (BCBS) की स्थापना 1974 में हुई थी।

• BCBS is headquartered at the Bank for International Settlements (BIS), Basel, Switzerland.

• BCBS का मुख्यालय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS), बेसल, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

• Pillar III complements Pillar I (Minimum Capital Requirements) and Pillar II (Supervisory Review Process) by improving transparency through public disclosures.

• पिलर III, पिलर I (न्यूनतम पूंजी आवश्यकता) और पिलर II (पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया) का पूरक है तथा सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाता है।

Ques: What is the name of the digital initiative launched by EPFO to trace and link old or inoperative PF accounts?

प्रश्न: पुराने या निष्क्रिय PF खातों का पता लगाने और उन्हें लिंक करने के लिए EPFO द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल का नाम क्या है?

A) EPF Connect / EPF कनेक्ट

B) Digi PF / डिजी PF

C) E-PRAAPTI / ई-प्राप्ति

D) EPFO Link / EPFO लिंक

E) PF Mitra / PF मित्र

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) will launch its 'E-PRAAPTI' digital platform by the end of the month to help subscribers trace, link, and access their old or inoperative EPF accounts.

• कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस महीने के अंत तक 'E-PRAAPTI' डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिससे सदस्य अपने पुराने या निष्क्रिय EPF खातों का पता लगा सकेंगे, उन्हें लिंक कर सकेंगे और उन तक आसानी से पहुँच सकेंगे।

• Currently, more than 30.91 lakh inoperative EPF accounts holding around ₹9,330 crore remain unclaimed. An EPF account becomes inoperative if no contribution is received for three consecutive years.

• वर्तमान में 30.91 लाख से अधिक निष्क्रिय EPF खाते हैं, जिनमें लगभग ₹9,330 करोड़ की राशि पड़ी हुई है। यदि किसी EPF खाते में लगातार तीन वर्षों तक कोई अंशदान नहीं होता, तो वह निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है।

• The Aadhaar-based platform will simplify account verification, enable automatic processing of eligible PF account mergers and withdrawals, and reduce dependence on physical paperwork and previous employers.

• आधार-आधारित यह प्लेटफॉर्म खाता सत्यापन को आसान बनाएगा, पात्र मामलों में PF खातों के विलय (Merger) और निकासी (Withdrawal) की प्रक्रिया को स्वचालित करेगा तथा कागजी प्रक्रिया और पूर्व नियोक्ताओं पर निर्भरता को कम करेगा।

• The initiative is part of EPFO Reform 2.01 and aims to improve member services while reducing paperwork and delays in accessing provident fund savings.

• यह पहल EPFO Reform 2.01 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सदस्य सेवाओं में सुधार करना तथा PF बचत तक पहुँचने में कागजी प्रक्रिया और देरी को कम करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• EPFO – Employees' Provident Fund Organisation
• EPFO – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
• Established – 1952
• स्थापना – 1952
• Act – EPF & MP Act, 1952
• अधिनियम – कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952
• Headquarters – New Delhi
• मुख्यालय – नई दिल्ली
• Chairperson – Union Labour Minister
• अध्यक्ष – केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री
• Purpose – Provident Fund Account Management and Social Security
• उद्देश्य – भविष्य निधि खातों का प्रबंधन एवं सामाजिक सुरक्षा

Ques: Which fund has been operationalised by IRDAI under Section 16A of the IRDA Act, 1999 to promote insurance literacy and protect policyholders?
प्रश्न: बीमा साक्षरता बढ़ाने और पॉलिसीधारकों की सुरक्षा के लिए IRDA अधिनियम, 1999 की धारा 16A के तहत IRDAI ने किस कोष को लागू (Operationalise) किया है?

A) Insurance Awareness Fund (IAF) / इंश्योरेंस अवेयरनेस फंड

B) Policyholders' Education and Protection Fund (PEPF) / पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष

C) Insurance Security Fund (ISF) / इंश्योरेंस सिक्योरिटी फंड

D) Policyholders' Welfare Fund (PWF) / पॉलिसीधारक कल्याण कोष

E) National Insurance Development Fund (NIDF) / राष्ट्रीय बीमा विकास कोष

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) approved a comprehensive reform package during its 137th Authority Meeting to modernise the insurance sector and strengthen policyholder protection.

• भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अपनी 137वीं प्राधिकरण बैठक में बीमा क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा पॉलिसीधारकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक सुधार पैकेज को मंजूरी दी।

• The reforms aim to improve insurance penetration, strengthen governance, and support the implementation of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025.

• इन सुधारों का उद्देश्य बीमा कवरेज (Insurance Penetration) बढ़ाना, सुशासन को मजबूत करना तथा सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन को समर्थन देना है।

• The key reform operationalises the Policyholders' Education and Protection Fund (PEPF) under Section 16A of the IRDA Act, 1999 to promote insurance literacy, grievance redressal, and recovery of unclaimed amounts.

• प्रमुख सुधार के तहत IRDA अधिनियम, 1999 की धारा 16A के अंतर्गत पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (PEPF) को लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य बीमा साक्षरता,

शिकायत निवारण तथा दावा न की गई राशि (Unclaimed Amounts) की वापसी को बढ़ावा देना है।

• A major feature of the reforms is the mandatory tagging of the authorised salesperson with every insurance proposal, policy, and certificate of insurance.

• सुधारों की एक प्रमुख विशेषता प्रत्येक बीमा प्रस्ताव, पॉलिसी और बीमा प्रमाणपत्र के साथ अधिकृत विक्रेता (Authorised Salesperson) का अनिवार्य टैगिंग करना है।

• The amendments also introduce perpetual registration for insurance intermediaries through an annual fee regime, replacing the earlier system of periodic renewals.

• संशोधनों के तहत बीमा मध्यस्थों के लिए आवधिक नवीनीकरण की व्यवस्था समाप्त कर वार्षिक शुल्क प्रणाली के माध्यम से स्थायी पंजीकरण (Perpetual Registration) की व्यवस्था की गई है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• IRDAI was established in 1999 under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

• IRDAI की स्थापना 1999 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत हुई थी।

• Headquarters – Hyderabad, Telangana.

• मुख्यालय – हैदराबाद, तेलंगाना।

• IRDAI is the statutory regulator responsible for regulating and promoting the insurance industry in India.

• IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन एवं विकास करने वाला वैधानिक नियामक है।

• The objective of PEPF is to enhance policyholder awareness, financial literacy, consumer protection, and efficient grievance redressal in the insurance sector.

• PEPF का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में पॉलिसीधारकों की जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और प्रभावी शिकायत निवारण को बढ़ावा देना है।

Ques: The Government is considering imposing a Merchant Discount Rate (MDR) of 25–35 bps on which UPI transactions?

प्रश्न: सरकार 25–35 बेसिस प्वाइंट (bps) का MDR किस प्रकार के UPI लेनदेन पर लगाने पर विचार कर रही है?

A) Transactions above ₹500 / ₹500 से अधिक के लेनदेन

B) Transactions above ₹1,000 / ₹1,000 से अधिक के लेनदेन

C) Transactions above ₹2,000 / ₹2,000 से अधिक के लेनदेन

D) Transactions above ₹5,000 / ₹5,000 से अधिक के लेनदेन

E) All UPI transactions / सभी UPI लेनदेन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Central Government is considering reintroducing a Merchant Discount Rate (MDR) of 25–35 basis points (0.25%–0.35%) on UPI transactions above ₹2,000 for large merchants.

• केंद्र सरकार बड़े व्यापारियों के ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर 25–35 बेसिस प्वाइंट (0.25%–0.35%) का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फिर से लागू करने पर विचार कर रही है।

• Merchants with an annual turnover of up to ₹1.5 crore are likely to remain exempt from the proposed MDR, irrespective of the transaction amount.

• ₹1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों को प्रस्तावित MDR से छूट मिलने की संभावना है, चाहे लेनदेन की राशि कितनी भी हो।

• The proposal aims to compensate banks and payment service providers for rising infrastructure and technology costs, while the necessary amendments are proposed through changes to the Payment and Settlement Systems Act, 2007.

• इस प्रस्ताव का उद्देश्य बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को बढ़ती तकनीकी एवं अवसंरचना लागत की भरपाई करना है। इसके लिए भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

• The proposed measure is intended to support banks and payment service providers by helping recover the growing cost of maintaining digital payment

infrastructure.

• इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य बैंकों एवं भुगतान सेवा प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान अवसंरचना के बढ़ते रखरखाव खर्च की भरपाई में सहायता प्रदान करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• UPI (Unified Payments Interface) – Launched by NPCI in 2016.
• UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) – NPCI द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया।
• NPCI – Established: 2008.
• NPCI – स्थापना: 2008।
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।
• The Government removed MDR on UPI and RuPay Debit Card transactions from 1 January 2020 to promote digital payments.
• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2020 से UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर MDR समाप्त कर दिया था।

Ques: HDFC Bank has launched which two specialised savings account variants for senior citizens and women?
प्रश्न: HDFC बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए कौन-से दो विशेष बचत खाते लॉन्च किए हैं?

A) Smart Senior & Smart Women / स्मार्ट सीनियर एवं स्मार्ट वूमेन

B) Elite Senior & Elite Her / एलीट सीनियर एवं एलीट हर

C) Max for Seniors & Max for Her / मैक्स फॉर सीनियर्स एवं मैक्स फॉर हर

D) Prime Senior & Prime Women / प्राइम सीनियर एवं प्राइम वूमेन

E) Secure Senior & Secure Her / सिक्योर सीनियर एवं सिक्योर हर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• HDFC Bank launched two specialised savings account variants — Max for Seniors and Max for Her — for senior citizens and women.

• HDFC बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए Max for Seniors और Max for Her नाम से दो विशेष बचत खाते लॉन्च किए।

• Max for Seniors offers benefits such as cyber fraud insurance, doorstep banking, additional 0.5% FD interest, and first-year Demat AMC waiver, while Max for Her provides health check-ups, accident insurance, and locker discounts.

• Max for Seniors में साइबर फ्रॉड बीमा, डोरस्टेप बैंकिंग, FD पर 0.5% अतिरिक्त ब्याज तथा पहले वर्ष का डिमैट AMC शुल्क माफ जैसी सुविधाएँ हैं, जबकि Max for Her में स्वास्थ्य जांच, दुर्घटना बीमा और लॉकर छूट जैसी सुविधाएँ दी गई हैं।

• The accounts are part of HDFC Bank's Savings Max portfolio and aim to attract customers through banking, insurance, healthcare, and lifestyle benefits.

• ये खाते HDFC बैंक के Savings Max पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य एवं लाइफस्टाइल सुविधाओं के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने का उद्देश्य रखते हैं।

• The initiative reflects the growing trend among banks to offer value-added services beyond traditional interest rates to attract and retain customers.

• यह पहल दर्शाती है कि बैंक अब केवल ब्याज दरों तक सीमित न रहकर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ और विशेष सेवाएँ भी प्रदान कर रहे हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• HDFC Bank – Established: 1994

• HDFC बैंक – स्थापना: 1994

• Headquarters – Mumbai

• मुख्यालय – मुंबई

• MD & CEO – Sashidhar Jagdishan

• एमडी एवं सीईओ – शशिधर जगदीशन

• Tagline – We Understand Your World

• टैगलाइन – We Understand Your World

Ques: Which two private equity firms sold a combined 2.33% stake in Paytm for ₹2,038 crore?
प्रश्न: ₹2,038 करोड़ में Paytm की 2.33% हिस्सेदारी बेचने वाली दो प्राइवेट इक्विटी (PE) फर्म कौन-सी हैं?

A) Sequoia Capital & SoftBank / सिक्वोइया कैपिटल एवं सॉफ्टबैंक
B) Tiger Global & Accel / टाइगर ग्लोबल एवं एक्सेल
C) SAIF Partners & Elevation Capital / SAIF पार्टनर्स एवं एलीवेशन कैपिटल
D) Temasek & BlackRock / टेमासेक एवं ब्लैकरॉक
E) General Atlantic & Warburg Pincus / जनरल अटलांटिक एवं वारबर्ग पिंकस

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Private equity firms SAIF Partners and Elevation Capital sold a combined 2.33% stake in Paytm's parent company, One 97 Communications, for ₹2,038 crore through open market transactions.
• प्राइवेट इक्विटी फर्म SAIF Partners और Elevation Capital ने Paytm की मूल कंपनी One 97 Communications में अपनी 2.33% हिस्सेदारी खुले बाजार (Open Market) में ₹2,038 करोड़ में बेची।
• A total of 1.49 crore shares were offloaded through block deals on the National Stock Exchange (NSE). SAIF Partners sold 2.17%, while Elevation Capital sold 0.16% stake.
• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ब्लॉक डील के माध्यम से कुल 1.49 करोड़ शेयर बेचे गए। इनमें SAIF Partners ने 2.17% तथा Elevation Capital ने 0.16% हिस्सेदारी बेची।
• The shares were sold at an average price of ₹1,367.80 per share, while several domestic and foreign institutional investors purchased the shares.
• ये शेयर औसतन ₹1,367.80 प्रति शेयर की कीमत पर बेचे गए, जिन्हें कई घरेलू एवं विदेशी संस्थागत निवेशकों (Institutional Investors) ने खरीदा।

• The transaction reflects continued institutional participation in One 97 Communications through large block deals in the secondary market.
• यह सौदा द्वितीयक बाजार (Secondary Market) में बड़े ब्लॉक डील के माध्यम से One 97 Communications में संस्थागत निवेशकों की निरंतर भागीदारी को दर्शाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Paytm Parent Company – One 97 Communications Ltd.
• Paytm की मूल कंपनी – One 97 Communications Ltd.
• Established – 2010
• स्थापना – 2010
• Founder – Vijay Shekhar Sharma
• संस्थापक – विजय शेखर शर्मा
• Headquarters – Noida, Uttar Pradesh
• मुख्यालय – नोएडा, उत्तर प्रदेश
• Listed On – NSE & BSE
• सूचीबद्ध – NSE एवं BSE

Ques: Through which stock exchange did the promoter entity of Adani Power sell 12.48 crore shares worth about ₹2,627 crore?
प्रश्न: अडानी पावर की प्रमोटर इकाई ने लगभग ₹2,627 करोड़ मूल्य के 12.48 करोड़ शेयर किस स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचे?

A) BSE / बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

B) NSE / नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

C) India INX / इंडिया INX

D) MCX / मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज

E) IFSC Exchange / IFSC एक्सचेंज

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• A promoter entity of Adani Power, Ardour Investment Holding Ltd, sold 12.48 crore shares (0.65% stake) through an open market block deal on the National Stock Exchange (NSE).
• अडानी पावर की प्रमोटर इकाई Ardour Investment Holding Ltd ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ओपन मार्केट ब्लॉक डील के माध्यम से 12.48 करोड़ शेयर (0.65% हिस्सेदारी) बेची।
• The transaction was valued at approximately ₹2,627 crore, with the shares sold at an average price of ₹210.50 per share.
• इस सौदे का कुल मूल्य लगभग ₹2,627 करोड़ रहा तथा शेयरों की बिक्री ₹210.50 प्रति शेयर के औसत मूल्य पर की गई।
• The deal reflects a promoter stake sale through the stock market and does not involve the issue of new shares by the company.
• यह सौदा प्रमोटर हिस्सेदारी की बिक्री है और इसमें कंपनी द्वारा नए शेयर जारी नहीं किए गए हैं।
• Such block deals are executed between institutional participants in the secondary market and generally do not change the company's share capital.
• इस प्रकार की ब्लॉक डील द्वितीयक बाजार में संस्थागत प्रतिभागियों के बीच होती है और सामान्यतः कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करती।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Adani Power Ltd. – Established: 1996
• अडानी पावर लिमिटेड – स्थापना: 1996
• Headquarters – Ahmedabad, Gujarat
• मुख्यालय – अहमदाबाद, गुजरात
• Founder – Gautam Adani
• संस्थापक – गौतम अडानी
• NSE – National Stock Exchange
• NSE – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
• NSE – Established: 1992
• NSE – स्थापना: 1992

Ques: Which global credit rating agency assigned RBL Bank its **first-ever investment-grade credit rating with a long-term issuer rating of Baa2**?
प्रश्न: किस वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने RBL Bank को पहली बार Baa2 **दीर्घकालिक जारीकर्ता (Long-term Issuer) रेटिंग के साथ इन्वेस्टमेंट-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग प्रदान की?**

A) Fitch Ratings / फिच रेटिंग्स

B) S&P Global Ratings / एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स

C) CRISIL Ratings / क्रिसिल रेटिंग्स

D) Moody's Ratings / मूडीज़ रेटिंग्स

E) ICRA Ratings / इक्रा रेटिंग्स

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• RBL Bank received its first-ever investment-grade credit rating from Moody's Ratings, with a long-term issuer rating of Baa2 and a short-term issuer rating of P-2.

• RBL Bank को पहली बार Moody's Ratings द्वारा इन्वेस्टमेंट-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई, जिसमें दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग Baa2 तथा अल्पकालिक जारीकर्ता रेटिंग P-2 दी गई।

• Moody's Ratings assigned a Stable Outlook to RBL Bank.

• Moody's Ratings ने RBL Bank को Stable Outlook (स्थिर दृष्टिकोण) प्रदान किया।

• The Stable Outlook reflects the expected long-term financial and strategic support from the bank's largest shareholder, Emirates NBD Bank.

• यह Stable Outlook बैंक के सबसे बड़े शेयरधारक Emirates NBD Bank से मिलने वाले दीर्घकालिक वित्तीय एवं रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है।

• Emirates NBD Bank strengthened RBL Bank's capital base through a primary capital infusion of approximately ₹26,000 crore (USD 2.75 billion), acquiring a 60% stake in the bank.

• Emirates NBD Bank ने लगभग ₹26,000 करोड़ (USD 2.75 बिलियन) की प्राथमिक

पूंजी निवेश (Primary Capital Infusion) के माध्यम से RBL Bank की पूंजी को मजबूत किया तथा बैंक में 60% हिस्सेदारी प्राप्त की।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• RBL Bank was established in 1943 as Ratnakar Bank Limited.
• RBL Bank की स्थापना 1943 में रत्नाकर बैंक लिमिटेड के रूप में हुई थी।
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra.
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।
• Moody's Ratings is one of the world's leading credit rating agencies.
• Moody's Ratings विश्व की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है।
• Emirates NBD Bank is headquartered in Dubai, United Arab Emirates (UAE).
• Emirates NBD Bank का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थित है।

Ques: After a gap of more than two decades, RBI has proposed to resume 'on-tap' licensing for which type of banks?
प्रश्न: दो दशकों से अधिक के अंतराल के बाद RBI ने किस प्रकार के बैंकों के लिए 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है?

A) Small Finance Banks / स्मॉल फाइनेंस बैंक

B) Payment Banks / पेमेंट बैंक

C) Regional Rural Banks / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

D) Urban Cooperative Banks / अर्बन कोऑपरेटिव बैंक

E) Local Area Banks / लोकल एरिया बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has issued draft guidelines to resume 'on-tap' licensing of Urban Cooperative Banks (UCBs) after a gap of more than 20 years.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 20 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (UCBs) के लिए 'ऑन-टैप' लाइसेंसिंग दोबारा शुरू करने हेतु मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।

• Only eligible Multi-State Cooperative Credit Societies (CCSs) with at least 10 years of operations, ₹10,000 crore deposits, and ₹300 crore net worth can apply for conversion into UCBs.

• केवल वे मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी (CCSs) आवेदन कर सकेंगी जिनका कम-से-कम 10 वर्ष का संचालन, ₹10,000 करोड़ जमा और ₹300 करोड़ की नेटवर्थ हो।

• RBI has also proposed to harmonise interest rate regulations on loans across all regulated entities to improve transparency in lending rates and strengthen consumer protection.

• RBI ने सभी विनियमित संस्थाओं के लिए ऋणों पर ब्याज दर संबंधी नियमों को एकरूप (Harmonise) करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे उधार दरों में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ता संरक्षण मजबूत होगा।

• The draft framework is aimed at strengthening the Urban Cooperative Banking sector by allowing financially sound cooperative credit societies to transition into regulated banks.

• इस मसौदा ढाँचे का उद्देश्य वित्तीय रूप से सक्षम सहकारी क्रेडिट सोसायटियों को विनियमित बैंकों में परिवर्तित होने का अवसर देकर शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करना है।

Ques: According to the IMF, in which financial year is India's economy projected to cross the $5 trillion mark?
प्रश्न: IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस वित्त वर्ष में 5 ट्रिलियन डॉलर का आँकड़ा पार करने का अनुमान है?

A) FY2026–27
B) FY2027–28
C) FY2028–29 (FY29)
D) FY2029–30
E) FY2030–31

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Finance Minister Nirmala Sitharaman informed the Rajya Sabha that, according to the International Monetary Fund (IMF), India's economy is projected to cross the $5 trillion mark in FY2028–29 (FY29).

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था FY2028–29 (FY29) में 5 ट्रिलियन डॉलर का आँकड़ा पार करने का अनुमान है।

• According to the IMF World Economic Outlook (April 2026), India's GDP at current prices is projected to reach around $5.1 trillion by 2028–29.

• IMF World Economic Outlook (अप्रैल 2026) के अनुसार, भारत का वर्तमान मूल्यों पर GDP वर्ष 2028–29 तक लगभग 5.1 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है।

• The Government has adopted a broad-based growth strategy focusing on agriculture, manufacturing, MSMEs, infrastructure, logistics, tax reforms, innovation, digitalisation, human capital and energy security to achieve this milestone.

• इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कृषि, विनिर्माण, MSMEs, अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, कर सुधार, नवाचार, डिजिटलीकरण, मानव पूंजी एवं ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित व्यापक विकास रणनीति अपनाई है।

• The projected milestone reflects India's continued economic expansion and its position among the world's fastest-growing major economies.

• यह अनुमान भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति तथा विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उसकी स्थिति को दर्शाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• International Monetary Fund (IMF) – Established: 1944
• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) – स्थापना: 1944
• Headquarters – Washington, D.C., USA
• मुख्यालय – वॉशिंगटन डी.सी., अमेरिका
• Managing Director – Kristalina Georgieva
• प्रबंध निदेशक – क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
• World Economic Outlook (WEO) – Flagship Report of IMF

• वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) – IMF की प्रमुख रिपोर्ट

Ques: Indian Bank recently approved nearly ₹500 crore of loans for which sector during its 120th Foundation Day celebrations?
प्रश्न: इंडियन बैंक ने अपने 120वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान लगभग ₹500 करोड़ के ऋण किस क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए?

A) Agriculture / कृषि

B) Housing / आवास

C) MSME / सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)

D) Education / शिक्षा

E) Infrastructure / अवसंरचना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Indian Bank approved nearly ₹500 crore worth of MSME loans during a credit outreach programme held in New Delhi as part of its 120th Foundation Day celebrations.
• इंडियन बैंक ने 120वें स्थापना दिवस समारोह के तहत नई दिल्ली में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में लगभग ₹500 करोड़ के MSME ऋण स्वीकृत किए।
• Sanction letters were handed over to 128 beneficiaries by MD & CEO Binod Kumar, reaffirming the bank's commitment to promoting the growth of the MSME sector.
• MD एवं CEO बिनोद कुमार ने 128 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे, जिससे MSME क्षेत्र के विकास के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
• The bank also launched the Unified MSME Portal, a digital platform designed to provide a seamless and integrated banking experience for MSME customers.
• बैंक ने Unified MSME Portal भी लॉन्च किया, जो MSME ग्राहकों को सहज एवं एकीकृत डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगा।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Indian Bank Headquarters – Chennai, Tamil Nadu.
• इंडियन बैंक का मुख्यालय – चेन्नई, तमिलनाडु।
• Established – 1907.
• स्थापना – 1907।
• MD & CEO – Binod Kumar.
• MD एवं CEO – बिनोद कुमार।
• Foundation Day Celebrated – 120th Foundation Day (2026).
• स्थापना दिवस – 120वाँ स्थापना दिवस (2026)।

Ques: The newly launched Magnum Equity Ex-Top 100 Long Short Fund has been launched by which Mutual Fund company?
प्रश्न: नया Magnum Equity Ex-Top 100 Long Short Fund किस म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है?

A) HDFC Mutual Fund / एचडीएफसी म्यूचुअल फंड

B) ICICI Prudential Mutual Fund / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड

C) SBI Mutual Fund / एसबीआई म्यूचुअल फंड

D) Nippon India Mutual Fund / निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड

E) Kotak Mahindra Mutual Fund / कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• SBI Mutual Fund has launched its second investment strategy under the Specialised Investment Fund (SIF) framework – Magnum Equity Ex-Top 100 Long Short Fund.
• SBI म्यूचुअल फंड ने Specialised Investment Fund (SIF) ढांचे के तहत अपनी दूसरी

निवेश रणनीति Magnum Equity Ex-Top 100 Long Short Fund लॉन्च की है।
• It is an open-ended fund that primarily invests in equity and equity-related instruments of companies outside the top 100 large-cap stocks.
• यह एक ओपन-एंडेड फंड है, जो मुख्य रूप से शीर्ष 100 लार्ज-कैप कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के इक्विटी एवं इक्विटी-संबंधित साधनों में निवेश करेगा।
• The fund also allows limited short exposure in equities through derivative instruments under the Long-Short strategy.
• यह फंड Long-Short रणनीति के तहत डेरिवेटिव साधनों के माध्यम से इक्विटी में सीमित शॉर्ट एक्सपोज़र की भी अनुमति देता है।
• The New Fund Offer (NFO) opened on 7 August and will close on 20 August.
• इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) 7 अगस्त से खुला है और 20 अगस्त को बंद होगा।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• SBI Mutual Fund – Established in 1987.
• SBI म्यूचुअल फंड – स्थापना 1987।
• SEBI Headquarters – Mumbai.
• सेबी का मुख्यालय – मुंबई।
• SIF – Specialised Investment Fund.
• SIF – स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड।

Ques: According to SEBI's FY26 Annual Report, the settlement collection in FY26 stood at?
प्रश्न: SEBI की FY26 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार FY26 में सेटलमेंट कलेक्शन कितना रहा?

A) ₹798.9 crore
B) ₹491.2 crore
C) ₹109.8 crore
D) ₹1,491.21 crore
E) ₹533 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to SEBI's FY26 Annual Report, settlement collections declined sharply to ₹109.8 crore in FY26 from ₹798.9 crore in FY25 due to a lower number of settlement applications.

• SEBI की FY26 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कम सेटलमेंट आवेदनों के कारण FY26 में सेटलमेंट कलेक्शन ₹109.8 करोड़ रह गया, जो FY25 में ₹798.9 करोड़ था।

• Appeals filed against SEBI orders before the Securities Appellate Tribunal (SAT) declined from 533 in FY25 to 429 in FY26.

• सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में SEBI के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की संख्या FY25 के 533 से घटकर FY26 में 429 रह गई।

• During FY26, SEBI initiated 221 insider trading investigations and 49 front-running investigations, while continuing action against market manipulation.

• FY26 के दौरान SEBI ने 221 इनसाइडर ट्रेडिंग तथा 49 फ्रंट-रनिंग मामलों की जांच शुरू की और बाजार में हेरफेर के मामलों पर कार्रवाई जारी रखी।

• SEBI also granted in-principle approval to NSE to settle certain past regulatory lapses, subject to the payment of ₹1,491.21 crore.

• SEBI ने NSE को कुछ पुराने नियामकीय उल्लंघनों के निपटारे के लिए ₹1,491.21 करोड़ के भुगतान की शर्त पर सैद्धांतिक (In-Principle) मंजूरी भी प्रदान की।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• SEBI (Securities and Exchange Board of India) is the securities market regulator of India.

• SEBI (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) भारत का प्रतिभूति बाजार नियामक है।

• Established – 12 April 1988 (Statutory Status – 30 January 1992).

• स्थापना – 12 अप्रैल 1988 (वैधानिक दर्जा – 30 जनवरी 1992)।

• Headquarters – Mumbai, Maharashtra.

• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र।

• Chairman – Tuhin Kanta Pandey.

• अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडे।

Ques: Bajaj General Insurance has signed an MoU with which company to explore a commercial insurance partnership in India?
प्रश्न: बजाज जनरल इंश्योरेंस ने भारत में वाणिज्यिक बीमा साझेदारी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किस कंपनी के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं?

A) Munich Re / म्यूनिख री

B) Lloyd's of London / लॉयड्स ऑफ लंदन

C) Swiss Re Corporate Solutions / स्विस री कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस

D) Allianz SE / एलियांज एसई

E) Berkshire Hathaway / बर्कशायर हैथवे

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Bajaj General Insurance and Swiss Re Corporate Solutions have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to explore a commercial insurance partnership in India.
• बजाज जनरल इंश्योरेंस और स्विस री कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस ने भारत में वाणिज्यिक बीमा साझेदारी की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
• The partnership combines Bajaj General Insurance's strong domestic market presence with Swiss Re's global risk management expertise.
• यह साझेदारी बजाज जनरल इंश्योरेंस की मजबूत घरेलू बाजार उपस्थिति को स्विस री की वैश्विक जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता के साथ जोड़ती है।
• The collaboration aims to provide innovative commercial insurance solutions for Indian businesses and strengthen risk protection.
• इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय व्यवसायों के लिए नवीन वाणिज्यिक बीमा समाधान उपलब्ध कराना और जोखिम सुरक्षा को मजबूत बनाना है।
• The partnership is expected to enhance underwriting capabilities, improve risk assessment, and support large corporate clients across various sectors.
• इस साझेदारी से अंडरराइटिंग क्षमता, जोखिम मूल्यांकन और विभिन्न क्षेत्रों के बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों को बेहतर बीमा सेवाएं मिलेंगी।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Bajaj General Insurance – A leading General Insurance Company in India.
• बजाज जनरल इंश्योरेंस – भारत की एक प्रमुख सामान्य बीमा कंपनी।
• Swiss Re Headquarters – Zurich, Switzerland.
• स्विस री का मुख्यालय – ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड।
• Swiss Re Established – 1863.
• स्विस री की स्थापना – 1863।
• Insurance Sector Regulator in India – IRDAI.
• भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक – IRDAI।
• IRDAI Headquarters – Hyderabad.
• IRDAI का मुख्यालय – हैदराबाद।

Ques: The India Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC) has been established by the Government of India, in consultation with the RBI, primarily for what purpose?

प्रश्न: भारत सरकार ने RBI के परामर्श से India Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC) की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की है?

A) To promote digital lending / डिजिटल ऋण को बढ़ावा देने के लिए

B) To regulate cryptocurrency transactions / क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को विनियमित करने के लिए

C) To strengthen the prevention and detection of cyber financial frauds in the digital payments ecosystem / डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान को मजबूत करने के लिए

D) To manage foreign exchange transactions / विदेशी मुद्रा लेनदेन का प्रबंधन करने के लिए

E) To issue digital currency / डिजिटल मुद्रा जारी करने के लिए

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India (RBI), has established the India Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC).

• भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परामर्श से India Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC) की स्थापना की है।

• The primary objective of IDPIC is to strengthen the prevention and detection of cyber financial frauds in the digital payments ecosystem.

• IDPIC का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान को मजबूत करना है।

• The corporation will function as a real-time fraud intelligence and alert-sharing platform for banks and financial institutions, enabling faster identification and prevention of fraudulent activities.

• यह संस्था बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए रियल-टाइम फ्रॉड इंटेलिजेंस एवं अलर्ट साझा करने वाले प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करेगी, जिससे धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान और रोकथाम संभव होगी।

• A Computer Security Incident Response Team for the Financial Sector (CSIRT-Fin) has also been established under the overall supervision of the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In).

• इसके साथ ही भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) के समग्र पर्यवेक्षण में वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (CSIRT-Fin) भी स्थापित किया गया है।

Ques: According to RBI's new loan recovery guidelines, during which time can lenders contact borrowers or guarantors?

प्रश्न: RBI के नए ऋण वसूली दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋणदाता उधारकर्ता या गारंटर से किस समय के बीच संपर्क कर सकते हैं?

A) 6:00 AM – 9:00 PM
B) 7:00 AM – 8:00 PM
C) 8:00 AM – 7:00 PM

D) 9:00 AM – 9:00 PM
E) Anytime / किसी भी समय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has issued comprehensive loan recovery guidelines to ensure fair treatment of borrowers and prevent harassment by banks and recovery agents.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऋण वसूली के दौरान उधारकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने तथा बैंकों और रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
• Under the new guidelines, lenders and recovery agents may contact borrowers or guarantors only between 8:00 AM and 7:00 PM. They must also avoid calls or visits during sensitive situations such as bereavement or medical emergencies.
• नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋणदाता और रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच ही उधारकर्ताओं या गारंटर से संपर्क कर सकते हैं। शोक या चिकित्सा आपातकाल जैसी संवेदनशील परिस्थितियों में संपर्क करने से भी बचना होगा।
• Banks are required to frame a transparent recovery policy, maintain records of recovery calls, ensure ethical conduct by recovery agents, and avoid incentive structures that encourage harsh recovery practices.
• बैंकों को पारदर्शी रिकवरी नीति बनानी होगी, रिकवरी कॉल का रिकॉर्ड रखना होगा, रिकवरी एजेंटों के लिए आचार संहिता सुनिश्चित करनी होगी तथा कठोर वसूली को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन ढांचे से बचना होगा।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Regulator – Reserve Bank of India (RBI).
• नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)।
• Effective Date – 1 January 2027.
• प्रभावी तिथि – 1 जनवरी 2027।

• Applicable To – Commercial Banks & NBFCs.
• लागू – वाणिज्यिक बैंक एवं NBFCs।

Ques: The Enforcement Directorate (ED) filed the chargesheet in the ₹107.24 crore Panchkula Municipal Corporation fraud case under which Act?
प्रश्न: ₹107.24 करोड़ के पंचकूला नगर निगम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने किस अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की?

A) Prevention of Corruption Act, 1988 / भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

B) Companies Act, 2013 / कंपनी अधिनियम, 2013

C) Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 / धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002

D) Banking Regulation Act, 1949 / बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

E) Benami Transactions Act, 1988 / बेनामी लेनदेन अधिनियम, 1988

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Enforcement Directorate (ED) filed a chargesheet under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 against former Kotak Mahindra Bank Deputy Vice President Pushpinder Singh and others in the ₹107.24 crore Panchkula Municipal Corporation fraud case.
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत पूर्व कोटक महिंद्रा बैंक डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पुष्पिंदर सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ₹107.24 करोड़ पंचकूला नगर निगम घोटाले में चार्जशीट दाखिल की।
• The accused allegedly diverted civic funds through unauthorised bank accounts by using forged documents and fake authorisation letters, and subsequently laundered the money.
• आरोपियों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और जाली प्राधिकरण पत्रों का उपयोग कर नगर निगम की राशि अनधिकृत बैंक खातों में स्थानांतरित की तथा धन शोधन

(Money Laundering) किया।

• During the investigation, the ED attached assets worth ₹131.13 crore, including luxury vehicles and immovable properties. The agency stated that it has secured the entire defrauded amount.

• जांच के दौरान ED ने ₹131.13 करोड़ मूल्य की संपत्तियां, जिनमें लग्जरी वाहन और अचल संपत्तियां शामिल हैं, कुर्क कीं। एजेंसी ने दावा किया कि जांच के दौरान गबन की पूरी राशि सुरक्षित कर ली गई है।

Static Facts | स्थैतिक तथ्य

• Enforcement Directorate (ED) – Established in 1956.
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) – स्थापना 1956।
• Headquarters – New Delhi.
• मुख्यालय – नई दिल्ली।
• Prevention of Money Laundering Act (PMLA) – Enacted in 2002.
• धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) – वर्ष 2002 में लागू।
• ED Director – Rahul Navin.
• ED के निदेशक – राहुल नवीन।

EXAM
Genius